श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जो बात उन्होंने कही है कि पूरे विश्व के साठ से ज्यादा प्रतिशत केसेस यू.पी. में हैं, यह सही है। यह पूरे विश्व में इस समय उन्नीस सौ इक्कीस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्नीस सौ इक्कीस में से सोलह सौ केसेस केवल भारत में पाए गए। पूरे विश्व का 83.2 प्रतिशत बनता है। इस सोलह सौ में से बारह सौ बयालीस अकेले यू.पी. में पाए गए। उन्होंने कहा कि सिक्सटी परसेंट से ऊपर यू.पी. का बनता है, यह बिल्कुल सही है। रोटरी इंटरनेशनल ने उन्हें यह अवार्ड दिया है। उन्होंने जो अब एफर्ट किए, जो मैंने इस चिट्ठी में पढ़कर बताए कि इतना खिलाफ हो जाने के बाद भी अगर वे यह कह रही हैं कि हम 2004 तक सुनिश्चित कर लेंगे और उन्होंने किया भी है, जिसे मैंने अभी पढ़कर सुनाया है, वे पूछ रही हैं कौन से स्टेप्स हैं तो मैंने उनके चीफ सेक्रेट्री की चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई है। इसमें उन्होंने यह लिखा है कि हमने तीस हजार लोगों की टीम बना दी है, हम इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण उन्हें यह अवार्ड मिला है।

Poverty among the tribals

*522. SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the percentage of population below poverty line is substantially higher amongst the tribes than the national average;

(b) if so, the details of Government's policy to lower the percentage; and

(c) the position in the present Budget to counter that as compared to last year's Budget?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The Ministry of Tribal Affairs supplements the schemes of the States and UTs by providing a cent per cent grant as Special Central Assistance to the Tribal Sub Plan for filling critical gaps under income generating projects, and granting loans through the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and State channelising agencies.

(c) An amount of Rs. 534.50 crores have been provided under the Budget of the Ministry of Tribal Affairs for the year 2003-04 as against Rs. 532.00 crores for these schemes during 2002-03.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Sir, the answer given by the hon. Minister is not a detailed one; it is a brief answer. I wanted to know the policy of the Government to finish the poverty of the BPL level tribal population in the country. As per the Planning Commission's estimate, the tribal population below the poverty line is 51 per cent, as against the national average of 37 per cent. So, until and unless the Government comes up with a special policy, and a special package is given to the tribal population, Government will not be able to do away with this problem of tribal population living below the poverty line. Will the hon. Minister state whether there is any special policy to solve this problem, which can be implemented within a stipulated time?

श्री जुएल उराम: सर, जनजातियों में गरीबों की संख्या ज्यादा है, यह मैंने स्वीकार किया है और यह सही तथ्य है। इनके इस गैप को पूरा करने के लिए टीएसपी एप्रोच, ट्रायबल सब-प्लान प्रोजैक्ट एप्रोच किया जा रहा है। मैंने यहां जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि उनके बीपीएल को कम करने के लिए स्पेशल सैन्ट्रल असिस्टेंस के रूप में 534 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और यह बजट का बढ़ोत्तरी के साथ प्रावधान है। यह निरन्तर प्रयास है। यह बीपीएल का जो गैप है यह ट्राइबल में ज्यादा है। यह आज का फिनोमिना नहीं है, बल्कि यह शुरू से है। अभी का लेटेस्ट फिगर जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, वह ऐसा नहीं है। 1999-2000 का 55वें राउंड का एनएसएस सर्वे बताता है 27.11 परसेंट जनरल का बीपीएल है। उस समय में जनजातियों में 34.76 है, 51 आगे था, अभी नहीं है। इससे घट रहा है और इसको कैसे घटाया जाए उसके लिए सरकार का निरंतर प्रयास है।

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, this answer does not come to grips with the problem. The hon. Minister has said that the proportion of people living below the poverty line in the tribal areas is much higher than the national average. The question is, are the resources that are being devoted for tribal development and welfare, adequate to bridge this gap or not? This answer, I think, is completely silent on that. Would the hon. Minister tell us whether the Rs. 534 crores of rupees that is allocated in the tribal sub-plan is adequate to meet the objectives of lifting the people in the tribal areas above the poverty line?

श्री जुएल उराम: सर, मैं मानता हूं कि यह जो अर्थ है, इसकी जितनी व्यवस्था की गई है वह इनसफीशिएंट है, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि राज्य सरकार को हम जो पैसा देते हैं वह खर्च नहीं हो पाता है। केन्द्र सरकार बजट का प्रावधान बढ़ा सकती है, लेकिन राज्य सरकार अगर उसको उस तरह खर्च नहीं करेगी तो हम बजट में बढ़ाकर क्या करेंगे। हालांकि केन्द्र सरकार की तरफ से हम 2-4 बार धमकी भी देते हैं कि आपका पैसा बंद कर देंगे या यह करेंगे, लेकिन फिर भी हम बंद नहीं करते हैं, बल्कि देते रहते हैं। इसलिए ये इसके दोनों पहलू हैं। मैं यह मानता हूं कि जो

सफीशिएंट पैसा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। अब इसमें आपका सुझाव कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो मेरा यह कहना है कि केन्द्र सरकार इसको बढ़ाने के लिए राज़ी है और वह हम दे सकते हैं।

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, the Planning Commission approved the tribal sub-plan for each State. For the hon. Minister to state that the States are not implementing the plan, I think, is a sad reflection on the planning process in our country.

श्री सभापति: ठीक है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वह इस बात की जानकारी रखते हैं कि आदिवासियों की आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा ऐसा है जो कि कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर है और वह ऐसा हिस्सा है जिसके पास जमीन नहीं है। जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उनसे पता चलता है कि जो किसान थे वे भी अपनी जमीन खो कर खेत मजदूर बनते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आप यह बतायेंगे कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सिर्फ पहला ही।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मेरा "क" सवाल यह है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: "क", "ख", "ग" नहीं चलेगा, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: क्या आप यह बतायेंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कि भूमि सुधार लागू नहीं हो रहे हैं? खुद योजना आयोग ने यह स्वीकारा है और जो टास्क फोर्स बना था, उसने स्वीकारा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर यह कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूंगी कि मंत्री जी इस संबंध में क्या कर रहे हैं। महोदय, इस संबंध में केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया है, वह बहुत ही खतरनाक है जिसके तहत तमाम आदिवासियों को उनकी जमीन से खदेड़ा जा रहा है। महोदय, जल, जमीन और जंगल आदिवासियों के जीवन के लिए मेन स्रोत हैं जिनसे उन्हें वंचित किया जा रहा है।

श्री सभापति : आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भूमि सुधार से आप का क्या मतलब है?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : भूमि सुधार से मतलब है कि भूमि रिकार्ड की जाए।

श्री सभापति : वह सब जगह रिकार्ड होती है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : रिकार्ड नहीं हो रही है। उन किसानों को भूमि नहीं मिली है।

श्री सभापति : आप बताइए जिससे कि भूमि सुधार क्रांतिकारी हो।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदय, क्रांतिकारी सुधार पश्चिम बंगाल ने किया है। इससे सीख लेनी चाहिए कि कैसे सुधार होना चाहिए क्योंकि कई जगह नकली नामों पर जमीन बंटी हुई है।

श्री सभापति: रिकार्ड तो सब जगह बनता है, अब वह सही बनता है या गलत बनता है, यह दूसरी बात है। आजकल तो रिकार्ड मॉडर्नाइज हो रहा है।

श्री जुएल उराम: सर, आदिवासी ज्यादातर जंगल और दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं। इसलिए जमीन उनके नाम नहीं होती है, उनके दखल में होती है। इस संबंध में सरकार की ओर से बार-बार राज्य सरकार को बताया गया है कि उनके नाम में जमीन के पट्टे होने चाहिए, उसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। अब जमीन नहीं है, उसके लिए हम ने दो-चार सरकार को डिमांड की है कि हम सरकार के पैसे से जमीन खरीद कर देंगे। महोदय, केरल और कर्नाटक को उसके लिए स्वीकृति भी दी है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, क्वैश्चन यह नहीं है, वह यह पूछ रही हैं कि जो जमीन आदिवासियों के नाम पर अलाट होती है, उसका रेगुलराइजेशन नहीं होता, उस के पट्टे नहीं मिलते, उसकी खातेदारी उन को नहीं मिलती।

श्री जुएल उराम: अगर ऐसा स्पेसिफिक केस बताएं तो हम देखेंगे।

* 523. [The questioner (Shri Ghulam Nabi Azad) was absent. For answer *vide* page 54-55 *infra.]*

* 524. [The questioner (Shri Matilal Sarkar) was absent. For answer *vide* page 55-57 *infra*]

Scheme for development of existing export infrastructure of Gujarat

*525. PROF ALKA BALRAM KSHATRIYA : Will the Ministrer of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is a scheme for development of the existing export infrastructure of Gujarat;

(b) if so, the details and the cost of the scheme;

(c) the Central aid or contribution released therefor; and

(d) the progress made in implementation of said scheme?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Department of Commerce has a scheme called "Assistance to State Governments for Development of Infrastructure for